प्रेषक.

अर्जुन सिंह, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांकः 1/3 जून, 2017 विषयः— उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पयेजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में 100 नग हैण्डपम्य अधिष्ठापन कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 942 / टी०ए०सी / 2017—18 दिनांक 12 मई,2017 एवं पत्र संख्याः 884 / वि०अनु० / 02 / शासन अनुदान / 2017—18 दिनांक 08 मई,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है संलग्न सूचीनुसार राज्य के विभिन्न जनपदों (गढ़वाल मण्डल में—52नग व कुमायूं मण्डल में 48नग) में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में 100नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य हेतु धनराशि रू० 233.00लाख(रू० दो करोड़ तैतीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2017—18 में लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित रू० 100.00लाख(रू० एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) हैण्डपम्प का अधिष्ठापन से पूर्व जिलाधिकारी की संस्तुति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाय।

(iii) रवीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च; 2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पन्न शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैंडयूल (ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आयणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें। हार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार्) ने स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवस्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के प्रशास

देये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम लेगा ब्रण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड ाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अधि रूसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। नर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला ावश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय। ण्डपम्प लगाते समय यदि हैण्डपम्प में पानी नहीं निकलता है(डाई बोर) तो थान पर नये प्रस्तावित स्थान का अनुमोदन भी जिलाधिकारी से प्राप्त 🛍 ायेगा ।

स सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या ति लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति कार्यकम-06-हैण्ड जलपूर्ति पम्पों अधिष्ठापन का 1-102-11से स्थान्तरित)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भा

डाला जायेगा।

नराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 1706130739 2 जून,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनाते 12/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च,2017 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश) क सुनिश्चित किया जाय।

ह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः 161 /XXVII(2)/2017 दिनांक में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

-हैण्डपम्पों के अधिष्ठान की जनपदवार सूची।

भवदीय.

(अर्जुन सिंह) अपर सचिव।

<u> 7.3 (1) / उन्तीस(2) / 17—2(14 पे0) / 2017, तदिनांक।</u> -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-।लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

लाधिकारी, देहरादून।

न्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

.ष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

ट निदेशालय, देहरादून।

। अनुभाग-2, उत्तराखण्डं शासन।

फाईल।

(अर्जन सिंह) अपर सचिव।

प्रेषक.

रोवा में

पैयजल एवं स विषय :-वित्ती महोदय.

2017 के रांत अन्तर्गत विभिन ष्रल रू० 147। अवशेष धनराहि धनराशि राज्य एखे जाने की ह

(i)

(ii) जिलाधिकारी दे

(iii) णायेगा। धनराहि में नहीं किया ज

(iv) अनुमोदन प्राप्त ः

अन्तर्गत शासकी प्राप्त कर ली ज ही धनराशि व्यय

(v)

vi) नियंत्रक / मुख्य / तो संबंधित वित्त

(vii) भौतिक प्रगति का कर दिया जाय। के समय प्रतिपूर्ति